

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2017/कार्तिक 3, 1939

No. 281]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2017/KARTIKA 3, 1939

# वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

## सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2017

सं. 36/2015-2020

विषयः ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्व अविध में विस्तार प्राप्त करने के संबंध में समयाविध की एककालिक छूट के संबंध में।

फा. सं. 18/42/एएम—18/पी—5.— विदेश व्यापार नीति, 2015—20 के पैरा 2.58 के साथ पठित पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्यों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार जनहित में एतद्द्वारा ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व में विस्तार प्राप्त करने से संबंधित प्रक्रियाओं में एककालिक छूट प्रदान करते हैं:

- 1. प्रक्रिया पुस्तक 2015—2020 के पैरा 5.17 (क) के अनुसार ''विदेश व्यापार नीति 2015—20 की अधिसूचना के पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र की निर्यात दायित्व अविध में विस्तार प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख को लागू एचबीपी खण्ड—1 के संगत प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगा''।
- 2. प्रक्रिया पुस्तक, 2015—2020 के पैरा 5.17 (ग) के अनुसार ''मूल निर्यात दायित्व अविध की समाप्ति की तारीख से 75 दिनों के भीतर क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात दायित्व अविध में विस्तार हेतु अभ्यावेदन करना होगा''।
- 3. जहां निर्यात दायित्व अविध (ईओपी) में विस्तार हेतु अभ्यावेदन निर्धारित समयाविध के बाद प्राप्त होते हैं, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी उन अभ्यावेदनों पर विचार नहीं कर पाते हैं। कई बार ऐसे अभ्यावेदन पहले ही

6393 GI/2017 (1)

कर लिए गए निर्यात के नियमितीकरण के लिए होते हैं। निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राप्त करने हेतु निर्धारित समयाविध के भीतर प्रस्तुत नहीं करने की इस अविध की छूट हेतु बड़ी संख्या में आवेदन विदेश व्यापार महानिदेशालय में रियायत हेतु प्राप्त होते हैं। इससे किठनाई आयी है तथा ईपीसीजी प्राधिकार पत्र बन्द करने में विलम्ब हुआ है। इसलिए प्रक्रिया की छूट में एककालिक उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय प्राधिकारी निर्यात दायित्व में विस्तार प्राप्त करने के लिए 5000/— रू० प्रति प्राधिकार पत्र अतिरिक्त संघटन शुल्क का भुगतान करने पर उन अभ्यावेदनों पर विचार कर सकता है जहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं किन्तु निर्धारित अविध के भीतर प्रस्तुत नहीं करने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया है। इस सुविधा के तहत क्षेत्रीय प्राधिकारी उन अभ्यावेदनों पर भी विचार कर सकता है जो 31.03.2018 तक प्राप्त हो सकते हैं। निर्यात दायित्व अविध का विस्तार मूल/विस्तारित समाप्ति अविध के क्रम में प्राधिकार पत्र जारी होने की तारीख को लागू प्रक्रिया पुस्तक के संगत प्रावधानों के अनुसार प्रदान किया जाएगा और यह विदेश व्यापार नीति तथा प्रक्रिया पुस्तक की अन्य सभी संगत शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा।

- 4. यह सुविधा निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध नहीं होगीः
  - ं. जहां ईपीसीजी प्राधिकार पत्र क्षेत्रीय प्राधिकारी/सीमा शुल्क प्राधिकारी/किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच के अधीन है/न्याय निर्णीत है।
  - ii. जहां ईपीसीजी समिति ने ऐसे विस्तार संबंधी अभ्यावेदनों को अस्वीकार कर दिया है।
  - iii. 01 सितम्बर, 2004 से पूर्व जारी ईपीसीजी प्राधिकार पत्र।
  - iv. जहां संस्थापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सार्वजनिक सूचना का प्रभावः ईपीसीजी के तहत निर्यात दायित्व अवधि में विस्तार प्राप्त करने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब की छूट हेतु एककालिक रियायत प्रदान की जा रही है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)
PUBLIC NOTICE
New Delhi, the 25th October, 2017

New Delhi, the 25th October, 2017 No. 36/2015-20

Subject: Onetime condonation of time period in respect of obtaining extension in Export Obligation period under EPCG Scheme.

- **F. No. 18/42/AM-18/P-5.** In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 read with Paragraph 2.58 of <u>FTP 2015-20</u>, the Director General of Foreign Trade in Public interest hereby makes the following one time relaxations in procedures in respect of obtaining extension in Export Obligation under EPCG Scheme.
- 1. As per Para 5.17 (a) of the Hand book of Procedures 2015-2020 "extension in Export Obligation Period of EPCG authorization issued prior to Notification of FTP 2015-20 shall be governed by relevant provisions of HBP Vol 1 applicable on the date of issue of authorization".
- 2. As per Para 5.17 (c) of the Handbook of procedures 2015-20 "request for extension in Export Obligation Period shall be made to RA within 75 days from the date of expiry of original EO Period".

- 3. Where the requests for extension in Export Obligation Period (EOP) are received beyond the prescribed time period, the RAs are not able to consider such requests. Many a times, such requests are for regularization of exports already done. A large number of requests for condonation of this period of non-submission within the prescribed time period for obtaining extension in EO Period are received in the DGFT for relaxation. This has caused hardship and delay in closure of the EPCG authorizations. Hence, as a onetime measure in relaxation of procedure, it has been decided that the RAs may consider requests for obtaining extension in Export Obligation period, where requests are received as per the prescribed procedure but have not been considered due to the non-submission within the prescribed period, on payment of additional composition fee of Rs. 5000/- per authorization. Under the facility RAs may also consider the requests that may be received upto 31.03.2018. The EOP extension would be granted as per the relevant provisions of HBP applicable on the date of issue of authorization in continuation of the original/extended expiry period, and would be subject to fulfillment of all other relevant conditions of the FTP and HBP.
- 4. This facility would not be available in the following cases:
  - i. Where the EPCG authorization is under investigation/ adjudicated by RA/customs authority/any other investigating agency.
  - ii. Where the EPCG committee has rejected such extension requests.
  - iii. The EPCG authorizations issued prior to 1<sup>st</sup> September, 2004.
  - iv. Where the installation certificate has not been submitted.

<u>Effect of the Public Notice:</u> Onetime relaxation for condonation of delay in submission of request for obtaining extension in Export Obligation period under EPCG is being provided.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade